

राजस्थान ने बिजली उत्पादन से लेकर पावर ट्रांसमिशन में हासिल की नई रफ्तार

कांग्रेस सरकार में विद्युत तंत्र रहा कुप्रबंधन का शिकार, उपभोक्ता बिजली को तरसे- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, प्रदेश की अपार सौर ऊर्जा क्षमता का प्रभावी उपयोग करने और भविष्य की बढ़ती बिजली आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। योजनाओं और नीतियों के समयबद्ध क्रियान्वयन से भाजपा सरकार ने 34 माह के कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के पहले 34 माह के साथ-साथ पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के कार्यों को कई गुना पीछे छोड़ बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

26 जिलों में दिन के समय में अज्जदाताओं को मिल रही बिजली

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बिजली उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि राज्य सरकार की नीतियों के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। आज हमारी सरकार के समय प्रदेश में 26 जिलों में अज्जदाताओं को दिन के दो ब्लॉक में बिजली मिल रही है। कस्बों से लेकर गांव-ढाणी तक गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय में विद्युत तंत्र कुप्रबंधन का शिकार रहा, डिस्कॉम घाटे में ही रहे और उपभोक्ता बिजली को तरसे।



बिजली उत्पादन में 10 हजार 920 मेगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि

प्रदेश में भाजपा की सरकार ने रोडमैप के तहत बिजली, पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर प्रतिबद्ध होकर कार्य किया है। परिणामस्वरूप गत 34 माह के कार्यकाल में राज्य के उपयोग के लिए बिजली उत्पादन क्षमता में 10 हजार 920 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में यह आंकड़ा 3 हजार 958 मेगावाट तक ही पहुंचा था। इस प्रकार भाजपा सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस की तुलना में पौने तीन गुना बिजली उत्पादन की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर कांग्रेस सरकार के पहले 34 महीनों की तुलना की जाए तो भाजपा सरकार का आंकड़ा लगभग 5 गुना से अधिक है।

राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा का हो रहा तेजी से विस्तार

राजस्थान में सौर ऊर्जा की व्यापक संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं पर कार्य करते हुए भाजपा सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और प्रदेशवासियों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है। जिसके परिणामस्वरूप 34 माह के कार्यकाल में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 28 हजार 303 मेगावाट की वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पहले 34 माह में यह वृद्धि मात्र 3 हजार 985 मेगावाट और पूरे पांच वर्ष में 14878 मेगावाट तक ही सीमित रही।

उच्च क्षमता वाले सब-स्टेशनों की हो रही तेजी से स्थापना

बिजली उत्पादन में वृद्धि के साथ सुचारु प्रसारण भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में उच्च क्षमता वाले विद्युत सब-स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने, विद्युत प्रसारण नेटवर्क के विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भाजपा सरकार के 34 माह के कार्यकाल में ही 400 केवी क्षमता के 2 ग्रिड सब-स्टेशन, 220 केवी क्षमता के 9 ग्रिड सब-स्टेशन, 132 केवी क्षमता के 51 ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष के पूरे कार्यकाल में 400 केवी क्षमता का एक, 220 केवी के पांच तथा 132 केवी 38 ग्रिड सब-स्टेशन ही स्थापित हुए थे। इसी प्रकार भाजपा सरकार के शासन में 33 केवी के 532 सब-स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं जबकि पूर्ववर्ती सरकार के 34 माह में 33 केवी के मात्र 477 सब-स्टेशन ही स्थापित हो पाये थे।

राजस्थान के विद्युत उत्पादन, सौर ऊर्जा क्षमता, विद्युत सब-स्टेशनों के विस्तार से जुड़े ये आंकड़े राज्य के ऊर्जा क्षेत्र की दिशा और विकास की संभावनाओं को सामने रखते हैं। ये सकारात्मक तस्वीर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ उद्योगों, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन उपलब्धियों के साथ राजस्थान विकसित भारत-विकसित राजस्थान के संकल्प की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

डिस्कॉम अब लाभ की स्थिति में

पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक 5.57 गीगावाट विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है जो कि देश में सर्वाधिक है। इस योजना से 3 लाख 78 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं, राजस्थान डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति इस सरकार के कार्यकाल में उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुई है। अजमेर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 825 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2025-26 में जयपुर डिस्कॉम ने 931 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

पंचायतीराज आम चुनाव के पहले चरण का मतदान आज, सरपंच पदों के लिए 1,525 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में

583 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए, किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ निर्विरोध निर्वाचन

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 1,525 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। जिले में कुल 2,119 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,108 वैध पाए गए। नाम वापसी के बाद 583 अभ्यर्थियों ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। किसी भी ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायत समिति चौमू की 34 ग्राम पंचायतों में 301, दूदू की 25 ग्राम पंचायतों में 136, गोविंदगढ़ की 27 ग्राम पंचायतों में 210, झोटवाड़ा की 19 ग्राम पंचायतों में 120, जोबनेर की 28 ग्राम पंचायतों में 232, किशनगढ़ रेनवाल की 26



ग्राम पंचायतों में 184, मौजमाबाद की 27 ग्राम पंचायतों में 185 तथा सांभर की 26 ग्राम पंचायतों में 157 अभ्यर्थी सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति चौमू में 394 नामांकन प्राप्त हुए तथा 93 अभ्यर्थियों ने नाम

वापस लिया। दूदू में 209 नामांकन प्राप्त हुए तथा 73 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया। गोविंदगढ़ में 303 नामांकन प्राप्त हुए तथा 90 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया। झोटवाड़ा में 161 नामांकन प्राप्त हुए तथा 39 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया। जोबनेर में 307 नामांकन प्राप्त हुए तथा 73 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया। किशनगढ़ रेनवाल

में 251 नामांकन प्राप्त हुए तथा 66 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया। मौजमाबाद में 262 नामांकन प्राप्त हुए तथा 77 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया। सांभर में 232 नामांकन प्राप्त हुए तथा 72 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया।

दिल्ली हाईकोर्ट: अदालत ने नेहा बोरा की याचिका की खारिज बॉन्ड भरने के लिए जारी किए नोटिस के खिलाफ दी थी अर्जी



एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने नेहा की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 130 के तहत शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नेहा बोरा को 16

अक्टूबर को मंडी हाउस में एक सभा में शामिल होने के दौरान हिरासत में लिया गया था। उनका आरोप है कि उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाकर आरके पुरम थाने में रातभर रखा गया और अगले दिन सुबह छह बजे रिहा किया गया। नोटिस में मंडी हाउस पर नारेबाजी, निषेधाज्ञा के बावजूद जंतर-मंतर के आसपास विरोध प्रदर्शन और कर्नाट प्लेस में प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। नेहा बोरा ने याचिका में कहा है कि नोटिस में शांति भंग होने की आशंका के समर्थन में कोई ठोस कारण, विशिष्ट घटना या समयावधि नहीं बताई गई है।

श्रद्धा को नहीं मिली जमानत, घटना को रिक्रिएट करेगी पुलिस

लखनऊ

शिवा हत्याकांड की आरोपी मॉडल श्रद्धा टुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश की जमानत अर्जी को प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। शिवा की हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, इसका पता करने के लिए पुलिस फोरेंसिक टीम की मदद से घटना का रिक्रिएशन करेगी। इसके लिए टीम तैयार कर ली गई है। उधर, कोर्ट में शुक्रवार को तीनों आरोपियों को जमानत देने की मांग वाली अर्जी दी गई। अर्जी में कहा गया कि तीनों आरोपी पूर्णतया निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि उन्हें इस मामले में झूठ फंसाया गया है। कोर्ट में आरोपियों की ओर से अलग-अलग दी गई जमानत अर्जियों पर कहा गया कि आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से फरार चल रहे थे। तीनों को नागपुर में महाराष्ट्र पुलिस एवं एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया था।

आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले सकती है पुलिस

श्रद्धा के पास से महज दो फोन बरामद हुए हैं। श्रद्धा की बहन रश्मि ने बयान में पुलिस को बताया कि उसका एक फोन नेपाल में कहीं गिर गया था। वहीं, श्रद्धा का भी एक फोन अभी बरामद नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि घटना के रिक्रिएशन और आरोपियों के फोन बरामदगी के लिए पुलिस तीनों को कस्टडी रिमांड पर लेगी। श्रद्धा का फोन मिलने के बाद उसके मददगारों का पता चल सकेगा।

आरोपियों को 31 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया था। वहीं, अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से फरार चल रहे थे। तीनों को नागपुर में महाराष्ट्र पुलिस एवं एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया था।

अगले नौ दिन संकट: दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर जहरीली एक्यूआई 200 पार, प्रदूषण में गुरुग्राम का योगदान सबसे अधिक

एजेंसी। नई दिल्ली

दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों की सेहत के लिए चिंता बढ़ाने लगी है। शुक्रवार को राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 230 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। आधिकारिक पूर्वानुमान के अनुसार, अगले नौ दिनों तक वायु गुणवत्ता में खास सुधार होने की संभावना नहीं है। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से फिलहाल रहत मिलने के आसार कम हैं।

56 में से 36 निगरानी केंद्रों पर हवा खराब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के आंकड़ों



के मुताबिक, दिल्ली के 56 निगरानी केंद्रों में से तीन पर हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। इसके बाद भी अगले छह दिनों तक स्थिति में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। एनसीआर के जिलों में गुरुग्राम का योगदान सबसे अधिक 8.8 प्रतिशत रहा। झज्जर 6.1 प्रतिशत और गौतमबुद्ध नगर 4.7 प्रतिशत के साथ अगले स्थानों पर रहे।

प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी

आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 20.3 प्रतिशत रही। इसके बाद आवासीय स्रोतों का योगदान 5.2 प्रतिशत, पराली जलाने का 5.1 प्रतिशत और उद्योगों का 4.2 प्रतिशत रहा। निर्माण गतिविधियों से 2.6 प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्र से दो प्रतिशत, कचरा जलाने से 1.8 प्रतिशत और सड़क की धूल से 1.4 प्रतिशत प्रदूषण दर्ज किया गया।

गाजियाबाद का योगदान 3.7 प्रतिशत और फरीदाबाद का 3.3 प्रतिशत दर्ज किया गया।

भविष्य के युद्धों के लिए 20-30 साल का विजन तैयार करे सेना: रक्षा मंत्री राजनाथ

एजेंसी। नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों से भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अगले 20 से 30 साल की दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारी करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सेना को केवल वर्तमान सुरक्षा खतरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बदलती तकनीक और युद्ध के आधुनिक तरीकों के अनुसार अपनी क्षमताओं का विस्तार करना होगा।

भू-राजनीतिक हालात और लचीली सैन्य रणनीति

रक्षा मंत्री ने वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य रणनीति ऐसी होनी चाहिए जो स्थिर न होकर गतिशील हो, ताकि बदलते हालात के अनुसार रणनीति में समय पर आवश्यक बदलाव किए जा सकें।

'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का उल्लेख

अपने संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता की विशेष रूप से सराहना



सेना को अगले 20-30 साल के लिए कैसी तैयारी करनी होगी?

रक्षा मंत्री ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे दुनिया और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे बदलावों का बारीकी से आकलन करें। युद्ध के तरीके तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए सेना की योजनाएं भी समय के साथ बदलनी चाहिए। उन्होंने सेना में पुनर्गठन के प्रयासों की सराहना करते हुए ड्रोन और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही, सैन्य क्षमताओं का लगातार आकलन करने और कमियों को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुधार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका असर सेना की वास्तविक संवर्धन क्षमता में भी दिखाई देना चाहिए।

की। उन्होंने कहा कि नए विचारों, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर तालमेल, मजबूत समन्वय और अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग ने इस अभियान को सफल बनाया। इस अभियान ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा।

तत्काल चुनौतियाँ और भविष्य की तैयारी का संतुलन

रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना की बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को तेजी से ढालने की क्षमता की तारीफ की। उन्होंने शीर्ष कमांडरों से कहा कि भविष्य की दीर्घकालिक योजनाओं के साथ-साथ तत्काल सामने आने वाली किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने की त्वरित क्षमता हमेशा बनी रहनी चाहिए।

चारू मीणा एपीआरओ से बनीं पीआरओ, जयपुर कलेक्ट्रेट में संभाला कार्यभार



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान द्वारा जारी पदोन्नति आदेश के तहत चारू मीणा को सहायक जनसंपर्क अधिकारी (एपीआरओ) से जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ), के पद पर पदोन्नत किया गया है। उल्लेखनीय है कि चारू मीणा वर्तमान में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, जयपुर में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं। विभागीय आदेश की अनुपालना में उन्होंने उपनिदेशक हेमंत सिंह को जनसंपर्क अधिकारी पद का कार्यग्रहण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जनसंपर्क अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। चारू मीणा की पदोन्नति पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, जयपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं इस दौरान मानसिंह मीणा (उपनिदेशक), राजेश भीमवाल, रतन लाल सैनी,जितेन्द्र कसाना, आशिमा सोनी, हितेश महरिया, अनिल सैनी, दिनेश सैनी, विशाल उपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने फागी में चुनाव पूर्व तैयारियों की समीक्षा की



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक की अध्यक्षता में उपखंड फागी में शुक्रवार को चुनाव पूर्व तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपखंड क्षेत्र में चिह्नित संवेदनशील मतदान बुथों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती तथा असामाजिक एवं अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी आवश्यक कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए जाएं। मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं में आपसी समन्वय तथा आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाए, ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। बैठक में पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण हनुमान प्रसाद मीणा, उपखण्ड अधिकारी बलबीर सिंह,तहसीलदार फागी, विकास अधिकारी फागी, वृत्ताधिकारी पुलिस तथा थानाधिकारी पुलिस थाना फागी उपस्थित रहे।

मदन राठौड़ बोले- परिवारवाद के नाम पर कब तक राजनीति

पिता-दादा का नाम लगाने की परंपरा; कहर- रेहान राजीव वाड़ा के नाम में पापा का नाम कहाँ

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। सांसद प्रियंका गांधी के बेटे रेहान राजीव वाड़ा की फोटो प्रदर्शनी के विवाद के बीच अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनके नाम को लेकर आपत्ति जताई है। मदन राठौड़ ने कहा- कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वह एक परिवारवाद के नाम पर कितने दिन राजनीति करेगी। उन्होंने कहा- वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए। फिर आप लोग कहेंगे कि विवादित बयान हो गया। आजकल रेहान को जो नाम दिया जा रहा है। उसे आप गुगल पर सर्च करेंगे तो रेहान राजीव वाड़ा आएगा। राठौड़ ने कहा- राजीव नाम क्यों, मतलब पापा कहाँ गए। यानी नाम कहाँ से कहाँ लगा रहे हो। क्योंकि उसी परिवार से राजनीति रीटियाँ सेकनी हैं। वह नाम साथ नहीं रहेगा तो राजनीति में जनता स्थान नहीं देगी। इसको विवादित कहो, कुछ भी कहो। लेकिन हमारे यहां मां, पिता और दादा का नाम लगाने की परंपरा है। खैर मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ।

कांग्रेस को राजनीति शिक्षा की जरूरत

मदन राठौड़ ने पीएम मोदी के राहुल गांधी पर दिए बयान का समर्थन किया। राठौड़ ने बताया- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि श्रीहरिकोटा स्थित हमारे स्पेस सेंटर से एक साल में जितने रॉकेट लॉन्च नहीं होते। उससे ज्यादा बार कांग्रेस अपने नेता को लॉन्च करने की असफल कोशिश कर चुकी है।

राठौड़ ने कहा- मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को प्रशिक्षण, राजनीतिक शिक्षा लेने की जरूरत है। इससे वह यह तय कर सके कि जनता की अपेक्षा क्या है। उसके अनुकूल चलना है, लेकिन वे ऐसे नहीं चलते हैं। वह किसी को तैयार करके लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, जो आगे जाकर फेल हो जाते हैं।

देश को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति ठीक नहीं

मदन राठौड़ ने कहा- हम सब देख रहे हैं कि कई लोग विदेश में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेतृत्व, योजनाओं और हमारी विदेश नीति कि बाहर जाकर अलोचना कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे देश को नुकसान पहुंचता है। राजनीति करने के लिए बहुत क्षेत्र हैं। राजनीति करो, लेकिन ऐसी राजनीति ठीक नहीं है, जिससे देश को नुकसान हो।

‘दीपावली उत्सव’ का भव्य एवं उत्साहपूर्ण समापन, 2,500 से अधिक आगंतुकों ने लिया हिस्सा

80 से अधिक स्टॉल्स पर सजे हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र; स्थानीय उत्पादों की खरीदारी को मिला जबरदस्त प्रोत्साहन

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जयपुर (शहर) द्वारा दीपावली के पावन अवसर पर 22 गोदाम स्थित परिसर में आयोजित दो दिवसीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी ‘दीपावली उत्सव’ का आज उत्साहपूर्ण समापन हुआ। प्रदर्शनी के दौरान 2,500 से अधिक आगंतुकों ने सहभागिता की, जबकि 80 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से स्थानीय शिल्पकारों एवं बुनकरों के उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया गया। अंतिम दिन भी शहरवासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला और उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स पर उपलब्ध पारंपरिक एवं हस्तनिर्मित उत्पादों की जमकर खरीदारी की। प्रदर्शनी में जयपुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के शिल्पकारों और बुनकरों द्वारा तैयार किए गए विविध पारंपरिक उत्पाद प्रमुख आकर्षण रहे। बगर एवं सांगनेरी ब्लॉक प्रिंट, बंधेज, विश्वप्रसिद्ध जयपुर ब्लू पॉटर, कुदून-मीनाकारी आभूषण, काष्ठ शिल्प, तारकशी कला, पारंपरिक चित्रकलाएं, मिट्टी के बर्तन, गृह सज्जा सामग्री तथा दीपावली पूजन सामग्री को आगंतुकों ने विशेष रूप से पसंद किया। उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि और उत्साहपूर्ण खरीदारी ने स्थानीय हस्तशिल्प की लोकप्रियता को

पिकसिटी प्रेस क्लब के 35वें स्थापना दिवस पर 26 पत्रकारों का सम्मान

एल.एल. शर्मा समेत छह को लाइफ टाइम अचीवमेंट, आठवले और दिया कुमारी रहे मौजूद

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। पिकसिटी प्रेस क्लब के 35वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को हुए मुख्य समारोह में 26 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार एल.एल. शर्मा समेत छह पत्रकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया। समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और विधायक गोपाल शर्मा शामिल हुए। क्लब अध्यक्ष मुकेश मीणा और महासचिव राजकुमार शर्मा ने बताया कि पत्रकारिता में योगदान के लिए एल.एल. शर्मा के अलावा प्रेम शर्मा, जसचंद बल, कुंजेश पतसरिया, शिवदयाल मिश्रा और राजेश पारीक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिए गए। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। रामदास आठवले ने पिकसिटी प्रेस क्लब को और भव्य रूप देने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग दिलाने की बात कही। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने

पत्रकार आवासीय योजना में फ्लैट की दरें 50% घटाने और 1,000 फ्लैट करने की मांग, ग्लोबल फोरम फॉर जर्नलिस्ट्स ने मुख्यमंत्री से किया आग्रह

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। ग्लोबल फोरम फॉर जर्नलिस्ट्स ने पत्रकार आवासीय योजना में फ्लैटों की प्रस्तावित दरें 50 प्रतिशत घटाने और योजना का दायरा बढ़ाकर 1,000 फ्लैट करने की मांग की है। फोरम का कहना है कि मौजूदा स्वरूप में योजना का फायदा वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारों तक पहुंचने की संभावना कम है। फोरम के संरक्षक जयदेव शर्मा, अध्यक्ष प्रद्युम्न शर्मा और सचिव अनिल माथुर ने संयुक्त बयान में पत्रकारों के लिए आवासीय योजना शुरू करने को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरोहनीय पहल बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादातर श्रमजीवी पत्रकारों का वेतन इतना नहीं है कि वे लाखों रुपए के फ्लैट खरीद सकें,

केंद्रीय मंत्री अठावले बोले- मोदी का विकेट उड़ाना राहुल के बस में नहीं, आंदोलन से सत्ता नहीं बदलती

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने कांग्रेस और विपक्ष के आंदोलनों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में आंदोलन के जरिए सरकार नहीं बदली जा सकती. सरकार बदलनी है तो जनता को मतदान के जरिए फैसला करना होगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी का विकेट उड़ाना राहुल गांधी के बस में नहीं है. अठवले शुक्रवार को जयपुर दौर पर रहे. इस दौरान उन्होंने पिक सिटी प्रेस क्लब के 35वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की. इस दौरान अठवले ने कांग्रेस पर क्रिकेट मैच का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं मोदी के साथ मिलकर 2029 में राहुल गांधी का विकेट लेने वाला हूँ, जहां तक मोदी को आउट करने की बात है तो राहुल गांधी कभी भी मोदी का विकेट नहीं उखाड़ सकते. उनके बस में नहीं है. आंदोलन से सरकार नहीं बदलती : अठवले ने जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को लेकर कहा कि जो भी जंतर-मंतर जाएगा, उसे अंदर जाना होगा. उनके इस बयान को विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की राजनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है. अठवले ने विपक्ष को संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का अधिकार जनता के पास है और इसका फैसला चुनाव के जरिए ही होना चाहिए. रामदास अठवले ने कहा कि लोकतंत्र में सभी



प्रदर्शित किया।

‘वोकल फॉर लोकल’ को मिला प्रोत्साहन

‘दीपावली उत्सव’ का मुख्य उद्देश्य स्थानीय दस्तकारों एवं बुनकरों को प्रत्यक्ष बाजार उपलब्ध कराना, उनके उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाना तथा उन्हें सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ना रहा। इस पहल ने पारंपरिक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ-साथ स्थानीय कारीगरों की आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रदर्शनी में 2,500 से अधिक आगंतुकों की सहभागिता और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी के प्रति उत्साह ने ‘वोकल फॉर लोकल’ एवं

पिकसिटी प्रेस क्लब के 35वें स्थापना दिवस पर 26 पत्रकारों का सम्मान

एल.एल. शर्मा समेत छह को लाइफ टाइम अचीवमेंट, आठवले और दिया कुमारी रहे मौजूद



कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। मदन राठौड़ ने क्लब के उन्नयन के लिए सहयोग का आश्वासन दिया, और सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने विधायक कोष से सहयोग की बात दोहराई।

समारोह में वरिष्ठ पत्रकार और क्लब के संस्थापक सदस्य प्रवीण चंद छाबड़ा समेत बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। स्थापना दिवस के तीन दिन के कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार को सूफी नाइट से हुई थी।



और मौजूदा दरें बनी रहें तो बड़ी संख्या में पात्र पत्रकार योजना से वंचित रह जाएंगे। फोरम ने मुख्यमंत्री से फ्लैटों की कीमत में 50 प्रतिशत कमी कर उसे करीब 35 लाख रुपए

करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि आगे निर्माण लागत या दूसरे कारणों से कीमत न बढ़ाई जाए। फोरम के मुताबिक जयपुर में बड़ी संख्या में पत्रकार वर्षों से आवास की समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए योजना में प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या बढ़ाकर 1,000 की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने 17 अक्टूबर को इस योजना का शुभारंभ किया था। राजस्थान आवासन मंडल की विशिष्ट पंजीकरण योजना-2026 के तहत जगतपुरा की इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, सेक्टर-9 में अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए बहुमंजिला फ्लैट्स का पंजीकरण शुरू हुआ है। पहले चरण में 3 बीएचके फ्लैट की कुल लागत में 15 लाख और 2 बीएचके में 12 लाख रुपए की छूट की घोषणा की गई थी।



को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन से सत्ता परिवर्तन की उम्मीद करना सही नहीं है. उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आंदोलन के कारण सरकारें बदलीं, लेकिन भारत की परिस्थितियाँ अलग हैं. भारत में सरकार बदलने का रास्ता चुनाव है और जनता अपने मताधिकार से सरकार चुनती है.

पुनाव आयोग पर आरोपों को बताया गलत

केंद्रीय मंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निशाना बनाकर उसे केंद्र सरकार से जोड़ना गलत है. विपक्ष सरकार को घेरने के लिए आयोग पर आरोप लगा रहा है. अठवले ने कांग्रेस पर दोहरे

मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीतती है, वहां वह वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाती. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने या मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगने से कोई फायदा नहीं होने वाला.

मतदाता सूची को लेकर भी दिया तर्क

अठवले ने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के मुद्दे पर कहा कि जो लोग दूसरी जगह चले गए हैं या लंबे समय से मतदान नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के नामों की समीक्षा की गई है. उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने मतदान नहीं किया है. हालांकि, इन दावों के समर्थन में उन्होंने कोई विस्तृत आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया. उन्होंने दोहराया कि चुनाव आयोग को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं है.

1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पात्र नागरिक जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में अपना नाम

ऑनलाइन-ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म 6 भरवाकर बीएलओ प्रदान करें पात्र नागरिकों को मताधिकार- जिला निर्वाचन अधिकारी



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु पात्र 18-19 आयु वर्ग के युवाओं सहित अन्य छूटे हुए पात्र नागरिकों के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने उक्त अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ के साथ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार 18-19 आयु वर्ग के युवाओं सहित अन्य छूटे हुए नागरिकों को मताधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से फार्म 6 भरवाकर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने सभी ईआरओ को निर्देशित किया है कि वे उनके क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में क्लस्टर कैप आयोजित कर बीएलओ के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची हेतु पात्र 18-19 आयु वर्ग के युवाओं को ऑफलाइन एवं <https://voters.eci.gov.in/> के माध्यम से ऑनलाइन फार्म अनिवार्य रूप से भरवाएँ। उन्होंने सभी ईआरओ को उनके क्षेत्र के बीएलओ को घर-घर भेजकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु पात्र नागरिकों के ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन फॉर्म 6 भरवाने के निर्देश प्रदान किए हैं ताकि देश की भावी पीढ़ी सहित छूटे हुए पात्र नागरिकों को मताधिकार प्रदान कर भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूती प्रदान की जा सके।

फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख ने पत्नी जेनेलिया के साथ अजमेर दरगाह में टेका माथा, नहीं दिया इन सवालों का जवाब



द अनकवर्ड अपडेट

अजमेर। बॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख शुक्रवार को अपनी पत्नी जेनेलिया डिस्जा और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे. यहां उन्होंने आस्था और सम्मान की चांदर चढ़ाई, मन्नत का धागा बांधा और चौखट पर मत्था टेक कर सलामीती की दुआ की. रितेश और जेनेलिया के साथ उनके दोनों बच्चे रियान व राहिल भी मौजूद थे. इसके अलावा रितेश के छोटे भाई धीरज देशमुख और उनकी पत्नी व फिल्म डायरेक्टर दीपशिखा भी मौजूद थीं. देशमुख परिवार ने दरगाह पर शुक्राने की चांदर चढ़ाई, परिवार में शांति, जीवन में सफलता और सलामीती की दुआ मांगी. रितेश ने दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली अपनी साउथ इंडियन फिल्म की कामयाबी को लेकर भी दुआ मांगी. हालांकि, प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो जाने के कारण रितेश और जेनेलिया के साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य कुछ देर के लिए असहज हो गए. दरगाह के खादिम ने इन सबको जियारत कराई, जबकि देशमुख फैमिली ने दरगाह पर कई रस्में भी अदा की. हालांकि, इस मौके पर पूरा परिवार चुपची साथे रहा और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.

राजस्थान में टोल बूथों पर वजन के नाम पर वसूली

बिना सर्टिफाइड कांटे पर कॉमर्शियल वाहनों का वजन करके वसूल रहे टोल



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राजस्थान में टोल बूथों और हाई-वे के पास संचालित धर्मकांड (बड़ी गाड़ियों के वजन करने वाले कांटे) पर बड़ी अनियमितताएं मिली हैं। इन पर बिना सर्टिफाइड करवाए कांटे (वजन नापने की मशीनें) से न केवल बड़े कॉमर्शियल वाहनों का वजन माप रहे हैं, बल्कि उनके आधार पर टोल टेक्स की वसूली की जा रही है। दो दिन (21, 22 अक्टूबर) में उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान की टीमों ने प्रदेश में ऐसे 380 धर्मकांडों का निरीक्षण किया, जहां टीम को 79 कांटे बिना सर्टिफाइड मिले। टीम ने जिन पर एक्शन लेकर 10.95 लाख रुपए का जुर्माना किया। अभियान के दौरान दौसा जिले के भांडारेज टोल प्लाजा पर बिना वैध सत्यापन के संचालित धर्मकांटे पाए जाने पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की। यहां स्थापित 16 धर्मकांडों को जब्त कर लिया गया, ताकि बिना सत्यापन की तौल प्रणाली के माध्यम से आगे किसी भी प्रकार की संभावित अनियमितता को रोका जा सके। इसके अलावा जालौर में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर सांगणा टोल प्लाजा पर, NH-248ए बहला टोल प्लाजा अलवर और टिंडियासर टोल प्लाजा NH-11 रतनगढ़ (चूरु) बने कांटे को जब्त करने की कार्रवाई की।

वजन से होता है टोल का निर्धारण

विभाग के डिप्टी कंट्रोलर आलोक जारवाल ने बताया कि जयपुर-आगरा हाई-वे पर ही भांडारेज टोल बूथ पर लगे 16 धर्मकांडों को जब्त किया गया। यहां बिना सर्टिफाइड वजन तोलने की मशीनें लगा रखी थीं। टोल प्लाजा पर भारी वाहनों से लिए जाने वाले टोल शुल्क का निर्धारण वजन के वजन के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यदि तौल उपकरण का वैध सत्यापन नहीं हुआ है, तो उसकी माप की शुद्धता सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती। गलत तौल के कारण वाहन का वजन वास्तविक वजन से अधिक दर्ज होने पर निर्धारित शुल्क से अधिक दर वसूल जाने की आशंका रहती है। इसके अलावा गलत तौल से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मालभाड़े और अन्य वजन आधारित भुगतानों पर भी प्रभाव पड़ता है।

जयपुर-अफेयर के शक में की थी लिव-इन पार्टनर की हत्या:पलैट में पड़ा मिला था महिला का शव; गिरफ्तारी से बचने बसों में करता रहा सफर



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। जयपुर में लिव-इन पार्टनर की हत्या मामले में पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने शुक्रवार सुबह खुलासा किया है। पुलिस ने फ्लैट में शव छोड़कर भागे आरोपी को भरतपुर से गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार बसों में सफर कर रहा था। पूछताछ में उसने अफेयर के शक में लिव इन पार्टनर की हत्या करना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से और भी पूछताछ कर रही है।

DCP (साउथ) राजर्षिराज ने बताया- हत्या में आरोपी युगराज सिंह उर्फ युवराज सिंह उर्फ दीपक (27) निवासी चिकसाना भरतपुर को अरेस्ट किया है। वह पिछले करीब एक साल से पत्रकार कॉलोनी रामपुरा की आमोर सोसायटी में रह रहा था।

इसी फ्लैट में वह लिव-इन पार्टनर मोना जाटव (35) के साथ रहकर टिफिन सेंटर चला रहा था। 18 अक्टूबर की देर रात आरोपी युवराज ने लिव-इन में रहने वाली मोना पर किसी भारी चीज से वार कर हत्या की थी।

मोबाइल बंद कर डाला

हत्या करने के बाद 19 अक्टूबर की सुबह करीब 6:30 बजे युवराज फ्लैट में शव छोड़कर भाग निकला। पुलिस से बचने के लिए मोबाइल आरोपी ने मोबाइल रिव्च ऑफ कर लिया। पुलिस ने उसे भरतपुर के बी.नारायण गेट से गुरुवार देर रात धर-दबोचा।

पुलिस से बचने के लिए वह मोबाइल बंद कर कभी दिल्ली, कभी आगरा तो कभी भरतपुर की बसों में घूमता रहा। वह फरारी कार्टने के लिए दिल्ली भागने की फिराक में था।

अफेयर के शक में मार डाला

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने लिव-इन पार्टनर मोना जाटव की हत्या करना कबूल किया है। उसने बताया कि उसे पिछले काफी समय से लिव-इन पार्टनर मोना पर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करने का शक था। दूसरे व्यक्ति से अफेयर होने के शक में उससे बात करने पर झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने मोना की हत्या कर दी।

पुलिस ने चोरी-नकबजनी की चार वारदातों का किया खुलासा, पांच चोरों सहित एक कबाड़ी गिरफ्तार

द अनकवर्ड अपडेट

आमेर। आमेर थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी की चार वारदातों का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कबाड़ खरीदने के बहाने गली-मोहल्लों में घूमते थे, बंद और सुनसान मकानों की रेकी करते थे और मौका मिलते ही चोरी करते थे। जांच में तीन अलग-अलग गिरोहों की भूमिका सामने आई है।

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि आमेर थाना क्षेत्र में कूकस स्थित निर्माणाधीन हॉस्टल, कुंडा तिराहे की एक बिजली की दुकान, दिल्ली रोड स्थित एक मैरिज गार्डन और एक बंद मकान में हाल के दिनों में चोरियां हुई थीं। इन मामलों के बाद थानाधिकारी राजेंद्र कुमार गोदारा के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और मुखबि्रों से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पुलिस के अनुसार 10 अक्टूबर को कूकस स्थित साईं वाटिका के निर्माणाधीन हॉस्टल से एसी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर पाइप और तार चोरी हुए थे। 18 अक्टूबर को कुंडा तिराहे पर स्थित एक इलेक्ट्रिकल दुकान से विभिन्न कंपनियों के बिजली के तार और नकदी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। इन दोनों मामलों में असलम और सुभान को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद चोरी का माल छिपाने और बेचने के आरोप में कबाड़ी पारसमल को भी गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली रोड पर गिल पैराडाइज मैरिज गार्डन से कॉपर वायर चोरी के मामले में रोहित ओझा और सोहेल खान उर्फ हसीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक आरोपी इकबाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। एक अन्य मामले में बंद मकान का ताला तोड़कर जेवरात, नकदी और घरेलू सामान चोरी करने के आरोप में मोहम्मद कासिम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बरामद सामान जब्त कर लिया गया है और पूछताछ में अन्य वारदातों तथा चोरी के माल की खरीद-फरोख्त से जुड़े लिंक भी खंगाले जा रहे हैं।

दो एसडीएम समेत 27 अफसरों पर चलेगा भ्रष्टाचार का केस

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। जयपुर 7 भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 27 अधिकारियों के खिलाफ 21 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने दो एसडीएम, एक डीएसपी, लेखा सेवा के अधिकारी और विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार के मुकदमे की मंजूरी दी है। एक मामले में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन के लिए नियम विरुद्ध रूपांतरित करने और भू-उपयोग परिवर्तन के जरिए सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। संबंधित उपखंड अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है। वहीं, खातेदारी भूमि के दावे में पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध डिग्री करवाने के मामले में एक अन्य उपखंड अधिकारी के खिलाफ भी अभियोजन की मंजूरी दी गई है।

विभागवार कार्रवाई में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के 5 मामले शामिल हैं। सार्वजनिक निर्माण के 3, वाणिज्यिक कर विभाग के 2 मामले में अभियोजन स्वीकृति दी गई है।

नकली नोट बनाने व सप्लाई मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 गिरफ्तार, ये वेबसीरीज देख आया था आइडिया

मास्टरमाइंड रवि मिश्रा के गुरु आनंद राजपूत ने यूट्यूब और फोटोशॉप के माध्यम से नकली नोट छापने का तरीका सीखा था.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

द अनकवर्ड अपडेट

डूंगरपुर। जिले की पुलिस साइबर सेल और विशेष टीम ने नकली नोट बनाने व सप्लाई करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले पुलिस दो आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपियों ने एक वेबसीरीज से नोट बनाने और सप्लाई का आइडिया लिया था. जिले के एसपी मनीष कुमार ने बताया कि गत 30 सितम्बर को रामसागडा थाना क्षेत्र के माड़ा स्कूल ग्राउंड से भावेश खटीक और नयन जोशी को 500-500 के 495500 रुपए मूल्य के जाली नोटों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों से पूछताछ के बाद यूपी निवासी रवि मिश्रा का नाम मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया. इधर पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही मुख्य मास्टरमाइंड रवि कुमार मिश्रा डूंगरपुर से फरार हो गया था.

जिला पुलिस की टीम ने लगातार लोकेशन

ब्रांड के हेलमेट निकालकर बेचते थे नकली माल:आरोपियों ने OLX पर सस्ते में बेचने का विज्ञापन दिया तो पकड़े गए , 10 लाख के हेलमेट बरामद

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर।जयपुर में हस्क्रू प्लेटफॉर्म के जरिए असली कंपनी के ब्लूटूथ वाले हेलमेट दिखाकर नकली हेलमेट बेचने का मामला सामने आया है। आरोपी कंपनी का असली हेलमेट निकालकर नकली हेलमेट बॉक्स में डालकर ग्राहकों को बेचते थे। इसके बाद असली हेलमेट हस्क्रू के जरिए सस्ती कीमत में बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हेडफॉक्स कंपनी के करीब 200 ब्लूटबथ वाले अस

ज्योति नगर थाना पुलिस ने हेडफॉक्स कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कंपनी के 200 से अधिक ब्लूटूथ हेलमेट बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। आरोपी कंपनी के असली हेलमेट की जगह दूसरी कंपनी के सस्ते हेलमेट ग्राहकों को भेजकर धोखाधड़ी कर रहे थे।

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि हेडफॉक्स इन्वोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि शुभम चौहान ने 19 अक्टूबर को ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

कंपनी हेडफॉक्स ब्रांड के ब्लूटूथ हेलमेट बनाती है। एक हेलमेट की बाजार कीमत करीब 4 हजार रुपए है। कंपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोडक्ट बेचती है। सुरेंद्र कुमार नागर (24) निवासी मूल रूप से ढोढसर, जयपुर ग्रामीण, हाल सूर्य नगर, मुरलीपुरा और सुशील कुमार बुराड़िया (27) निवासी सीकर, हाल गणेश नगर-2, न्यू करणी कॉलोनी, हरमाड़ा को गिरफ्तार किया है।

दो दिन (21, 22 अक्टूबर) में उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान की टीमों ने प्रदेश में ऐसे 380 धर्मकांटों का निरीक्षण किया, जहां टीम को 79 कांटे बिना सर्टिफाइड मिले। टीम ने जिन पर एक्शन लेकर 10.95 लाख रुपए का जुर्माना किया।

दौसा जिले के भांडारेज टोल प्लाजा पर बिना वैध सत्यापन के संचालित धर्मकांटे पाए जाने पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की। दौसा जिले के भांडारेज टोल प्लाजा पर बिना वैध सत्यापन के संचालित धर्मकांटे पाए जाने पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान दौसा जिले के भांडारेज टोल प्लाजा पर बिना वैध सत्यापन के संचालित धर्मकांटे पाए जाने पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की। यहां स्थापित 16 धर्मकांटों को जब्त कर लिया गया, ताकि बिना सत्यापन की तौल प्रणाली के माध्यम से आगे किसी भी प्रकार की संभावित



बदल रहे रवि मिश्रा का 1300 किलोमीटर तक 3 दिनों तक पीछा कर उसे लुधियाना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड रवि मिश्रा से उसके अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ की. पूछताछ और साइबर सेल के तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस टीमों को अलग-अलग राज्यों में भेजा गया. पुलिस की अलग-अलग टीमों ने अम्बाला, हरियाणा निवासी आनंद राजपूत को गिरफ्तार किया. आनंद ने रवि मिश्रा को अलीबाबा से कागज मंगवाकर नोट बनाने का ज्ञान दिया था.

एसपी ने बताया कि टेलीग्राम पर ‘अंकित पेपर सेलर’ चैनल चलाकर जाली नोट

शुरू की।

ज्योति नगर थाना प्रभारी गुंजन सोनी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी सुरेंद्र कुमार नागर ने हस्क्रू पर हेडफॉक्स कंपनी के हेलमेट बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचने का विज्ञापन दिया था। पुलिस ने सुरेंद्र को पकड़कर पूछताछ की तो ई-कॉमर्स कंपनी में काम करने वाले एक अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आई। आरोप है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले हेडफॉक्स के असली हेलमेट निकाल लिए जाते थे। उनकी जगह दूसरी कंपनी के कम कीमत वाले हेलमेट ग्राहकों को भेज दिए जाते थे। ग्राहक जब गलत उत्पाद मिलने की शिकायत के साथ सामान लौटाते, तो हेडफॉक्स कंपनी को नुकसान होता था। वहीं, असली हेलमेट दूसरे ग्राहकों को कम कीमत पर बेच दिए जाते थे।

200 से ज्यादा हेलमेट मिले

पुलिस ने इस मामले में सुरेंद्र कुमार नागर (24) निवासी मूल रूप से ढोढसर, जयपुर ग्रामीण, हाल सूर्य नगर, मुरलीपुरा और सुशील कुमार बुराड़िया (27) निवासी सीकर, हाल गणेश नगर-2, न्यू करणी कॉलोनी, हरमाड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 200 से अधिक हेडफॉक्स हेलमेट बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

राजस्थान में टोल बूथों पर वजन के नाम पर वसूली:बिना सर्टिफाइड कांटे पर कॉमर्शियल वाहनों का वजन करके वसूल रहे टोल

द अनकवर्ड अपडेट



अनियमितता को रोका जा सके। जालोर में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर सांगाणा टोल प्लाजा पर बने कांटे को जब्त करने की कार्रवाई की गई। जालोर में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर सांगाणा टोल प्लाजा पर बने कांटे को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा जालोर में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर सांगाणा टोल प्लाजा पर, ह्हा-248 बहला टोल प्लाजा अलवर और टिंडियासर टोल प्लाजा ह्हा-11 रतनगढ़ (चूरू) बने कांटे को जब्त करने की कार्रवाई की।

वजन से होता है टोल का निर्धारण

विभाग के डिट्री कंट्रोलर आलोक जारवाल ने बताया कि जयपुर-आगरा हाई-वे पर ही

गिरफ्तारी से पहले नोटिस नहीं दिया-जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई:कोर्ट ने कहा-7 साल की सजा के मामलों में नोटिस देना जरूरी, आरोपियों को जमानत मिली



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में सरस ब्रांड के नाम पर नकली पैकिंग सामग्री बनाने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जयपुर महानगर द्वितीय की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने कानूनी प्रावधानों की पालना किए बिना आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसे में कोर्ट ने पुलिस रिमांड देने से इनकार करते हुए आरोपियों को तुरंत जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में जांच अधिकारी (एसीपी झोटवाड़ा) की घोर लापरवाही मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए हैं।

7 साल तक की सजा के मामलों में नोटिस देना जरूरी

कोर्ट ने कहा कि अपवाद की स्थिति को छोड़कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत 7 साल तक की सजा के मामलों में आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उसे नोटिस दिया जाना जरूरी है। लेकिन इस मामले में केस डायरी से ऐसा कोई आधार या पर्याप्त कारण जाहिर नहीं हुआ कि यह नोटिस क्यों नहीं दिया गया। अदालत ने इसे आरोपियों के विधिक व संवैधानिक अधिकारों का स्पष्ट हनन तथा अनुसंधानाधिकारी की ‘घोर लापरवाही’ माना।

पुलिस थाना झोटवाड़ा में 29 सितंबर को दर्ज एफआईआर के अनुसार, सरस डेयरी जयपुर के गुणवत्ता नियंत्रण प्रभारी के मौखिक आदेश पर निवारू रोड, झोटवाड़ा स्थित एक स्थान पर औचक निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान वहां सरस ब्रांड के नाम पर नकली मोनोकार्टन, पॉलिपैक, प्रिंटिंग मशीन और स्कैनर भारी मात्रा में तैयार किए जाते हुए पाए गए। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने नामजद आरोपी श्यामसुंदर उर्फ श्याम सिंह चौहान और प्रमोद कुमार खंडेलवाल को गिरफ्तार किया था।

नकली कलाकंद बनाने में फंसाने की धमकी, 2 लाख घूस ली; 2 कांस्टेबल गिरफ्तार, अवैध हथियार भी जब्त



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। जयपुर नकली कलाकंद बनाने में फंसाने और फैक्ट्री सीज कराने की धमकी देकर 2 लाख की रिश्वत लेने वाले खैरथल-तिजारा डीएसटी के कांस्टेबल ब्रजेश और ईश्वर सिंह को एसीबी ने शुक्रवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। डीएसटी प्रभारी गौरव की भूमिका की भी जांच हो रही है। एसीबी एसपी पीयूष दीक्षित के अनुसार, परिवारी ने दो दिन पहले शिकायत दी थी। आरोप है कि 20 अक्टूबर को डीएसटी प्रभारी गौरव और दोनों कांस्टेबल सादे कपड़ों में उसके कारखाने पहुंचे। सीसीटीवी कैमरे हटवाकर नकली कलाकंद बनाने के आरोप में फंसाने की धमकी दी। पीछे-पीछे पहुंची खाद्य सुरक्षा टीम ने कलाकंद के सैंपल भी लिए। ब्रजेश ने माल नष्ट कराने और फैक्ट्री सीज होने से बचाने के बदले 1 लाख रु. मांगे। ईश्वर सिंह ने परिवारी के 3 परिचित कारोबारियों से 50-50 हजार लेकर डीएसटी कार्यालय आने का दबाव बनाया। कुल 2.20 लाख रुपए मांगे गए। बाद में परिवारी से 70 हजार और तीन अन्य कारोबारियों से 50-50 हजार रुपए देने को कहा गया। दूसरी और, एसीबी टीम ने बैरक की तलाशी ली। यहां एक अन्य कांस्टेबल के बैग से देशी पिस्टल और कारतूस मिले, जबकि दूसरे के बैग से 1.20 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई।



सम्पादकीय

“मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो विस्तारस्वतंत्रता का हग्न न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार”

गंभीर संगठित अपराध बना मानव तस्करी

यौन शोषण पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास को लेकर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश

कानूनी प्रावधानों की यदि बात की जाए तो अनेकित व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन पर आधारित था, जिसका मुख्य उद्देश्य यौन शोषण पर लगाम लगाना था, परंतु इस कानून में मानव-तस्करी की स्पष्ट परिभाषा का अभाव था। इसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2013 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मानव तस्करी के प्रावधान जोड़े गए, जो अंतरराष्ट्रीय पालेरमो प्रोटोकॉल के बिल्कुल अनुरूप हैं। मौजूदा समय में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत भी मानव तस्करी को एक संगठित अपराध के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। इसके बावजूद, जमीनी स्तर पर पीड़ितों की सुरक्षा, उनकी निजता और पुनर्वास को लेकर कई तरह की कमियां बनी हुई थीं, जिन्हें दूर करने के लिए गैर-सरकारी संस्था प्रज्वला द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इन नए निर्देशों में इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया गया है कि वेश्यावृत्ति या यौन शोषण के लिए मानव-तस्करी से मुक्त कराई गई किसी भी पीड़ित महिला के साथ भूलकर भी अपराधी जैसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस कार्रवाई के दौरान उनकी निजता का पूर्ण सम्मान होना चाहिए और उन्हें मीडिया के सामने बिल्कुल भी पेश न किया जाए। पुछताछ के वक्त हमेशा महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है तथा यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि वह स्थिति जबरन थोपी गई थी या नहीं। इसके अलावा, किसी भी पीड़िता को संरक्षण गृह भेजने या उसके परिवजनों को सौंपने से पहले उसकी सहमति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि संरक्षण गृहों का परिवेश और वहां मिलने वाली सुविधाएं बेहद बेहतर और मानवीय होनी चाहिए। न्यायालय के निर्देशानुसार अब प्रत्येक राज्य में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को मानव-तस्करी विरोधी ब्यूरो का प्रभारी बनाया गया है, जबकि %पीड़ित सुरक्षा योजना% को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को सौंपी गई है। इसके साथ ही रेड और रेस्क्यू अभियान चलाने वाली टीम के प्रभारी डीएसपी स्तर के अधिकारी होने चाहिए, जिसमें महिला अधिकारियों और गैर-शासकीय सलाहकारों को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक संसद इस विषय पर कोई नया और व्यापक कानून नहीं बना लेती, तब तक ये सभी विस्तृत निर्देश देश भर में अनिवार्य रूप से लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कानूनों और संस्थागत ढांचे की गहन समीक्षा करते हुए इनमें कई आवश्यक संशोधनों के भी सुझाव दिए हैं। अदालत का मानना है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत पीड़ित महिलाओं को अपराधी न माना जाए, संरक्षण गृहों के डिटेन्शन आधारित मॉडल के विकल्प तलाशे जाएं, और पुलिस द्वारा पीड़िताओं के समय पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न किए जाने की लापरवाही को दंडनीय अपराध बनाया जाए। अंततः, संविधान हर नागरिक को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत पुनर्वास भी शामिल है। इसलिए राज्य सरकारों का यह संवैधानिक और नैतिक दायित्व है कि वे मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए संवेदनशील पुलिस तंत्र, बेहतर संरक्षण गृह और पुख्ता पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित करें।

समझदारी से जीना भी एक कला है: खुद को समझें... असहमति के बावजूद दूसरों का सम्मान करें



जीवन की कठिनाइयों के बीच विवेक बनाए रखना ही असली परिपक्वता है; आत्म-चिंतन और सहनशीलता से बदलता है जीने का नजरिया

हिन्दी समाचार पत्र

द अनकवर्ड अपडेट

कवर के पीछे की खबर

Digital Edition | RJHIN/25/A4779

सच जो छुपा था, अब सामने है

जमीनी हकीकत विश्लेषण के साथ जनहित के मुद्दे सत्ता से सवाल

ई-पेपर पढ़ने के लिए विजिट करें

www.hpnews.in

www.theuncoveredupdate.com

राजस्थान देश दुनिया की बेबाक खबरें

सिर्फ खबर नहीं सच्चाई की खोज

सच तथ्य जांच जनहित

आस्था जुटाने की तैयारी तो है, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने की योजना कहां है

भारत जैसे देश में धार्मिक आयोजनों, प्रसिद्ध तीर्थस्थलों, मेलों और उत्सवों का आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूप से अत्यंत विशेष महत्त्व रहा है। इन आयोजनों में उमड़ने वाली अपार जनसमूह और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने के साथ-साथ सामाजिक एकता को भी मजबूत करती है। परंतु, विडंबना यह है कि जब भी ऐसे आयोजनों में कुप्रबंधन, भगदड़, आग लगने की घटनाओं या अन्य भीषण हादसों के कारण मासूम लोगों की जान चली जाती है, तब देश की व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ के दौरान 19 लोगों की दर्दनाक मौत और इसके तुरंत बाद बिहार के सीवान जिले में दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक आग लगने से पांच बच्चों समेत कम से कम 10 लोगों के बुरी तरह झुलस जाने की घटनाओं ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। इन तमाम त्रासदियों के बीच सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और भव्य गलियारे विकसित करने के लिए नई-नई योजनाएं और बड़े बजट आवंटित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों और आयोजनों में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले

रहा है देशभर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले धार्मिक आयोजनों और मेलों में घटित होने वाली इन दुर्घटनाओं के कारणों का यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए, तो लगभग हर बार एक जैसी ही प्रशासनिक और प्रबंधकीय दोष सामने आते हैं। जांच समितियों की रिपोर्ट में अमूमन यही तथ्य उभर कर आते हैं कि एक ही स्थान पर तय क्षमता से कई गुना अधिक श्रद्धालुओं का पहुंचना, सीमित जगह, आवाजही के लिए संकरे रास्ते, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस या स्वयंसेवकों के माकूल इंतजामों का अभाव, बिजली के तारों का जाल तथा आग बुझाने के पर्याप्त उपकरणों का न होना जैसी बुनियादी कमियां इन हादसों की मुख्य वजह बनती हैं। कई मामलों में स्थानीय आयोजक आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित संख्या का सही और वैज्ञानिक आकलन करने में पूरी तरह विफल रहते हैं, जिसके कारण प्रवेश और निकास के रास्ते आपात स्थिति के लिहाज से अत्यंत अपर्याप्त साबित होते हैं। इसके अलावा, कई बार मामूली अफवाहें फैलने से भी स्थिति इतनी बेकाबू हो जाती है कि लोगों की जान पर बन आती है। बिहार के

सीवान में हुए अग्निकांड की तकनीकी वजह भले ही स्पष्ट हो रही हो, लेकिन यह यक्ष प्रश्न अपनी जगह कायम है कि आखिर आपात स्थिति से निपटने के लिए वहां पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे और आग लगने पर महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के वैकल्पिक मार्ग क्यों उपलब्ध नहीं थे? धार्मिक आयोजनों से जुड़ी इस लापरवाही का दायरा केवल बंगाल या बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। अभी पिछले सप्ताह ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित शीतला माता मंदिर के बाहर सड़क पार कर रहे श्रद्धालुओं को एक तेज रफ्तार ट्रक द्वारा कुचल दिए जाने की हृदयविदारक घटना में 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। धार्मिक स्थलों और आयोजनों पर आए दिन होने वाले ऐसे हादसे हमारी लचर व्यवस्था, योजना के अभाव और नागरिकों की बहुमूल्य सुरक्षा के प्रति प्रशासनिक उदासीनता को बेनकाब करते हैं। विडंबना यह है कि इन त्रासदियों के घटित होने के बाद केवल औपचारिकता निभाई जाती है। सरकार की तरफ से त्वरित रूप से उच्चस्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और

दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बड़े-बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों बाद वह जांच फाइलें सरकारी दफ्तरों के उंडे बस्ते में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। सवाल यह है कि इस प्रकार के जानलेवा हादसों के घटित होने का इंतजार करने के बजाय उनके निवारण के लिए पहले से ही एक फूल-फूफ और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती है? यह स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि सरकारी और स्थानीय प्रशासन किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन में अपनी तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर सारा दारोमदार केवल निजी आयोजनों या समितियों पर नहीं छोड़ सकते। इस दिशा में तत्काल प्रभाव से देश भर के सभी धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए बहुत ही स्पष्ट, पारदर्शी और सख्त सुरक्षा मानक लागू किए जाने की सख्त आवश्यकता है। किसी भी बड़े आयोजन या मेले की अनुमति देने से पहले प्रशासन के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह स्थल की वास्तविक क्षमता, श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या, आपातकालीन निकास मार्गों, अग्निशमन तंत्र और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की कड़ी जांच करे। आस्था का वास्तविक सम्मान और संरक्षण तभी संभव हो सकता है, जब ऐसे आयोजनों में मत्था टेकने या शामिल होने वाला प्रत्येक नागरिक शाम को पूरी तरह सुरक्षित अपने घर वापस लौट सके।

ट्रंप पर कितना भरोसा करें

बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत-अमेरिका व्यापारिक रिश्तों के नए समीकरण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, जिनमें वे भारत के साथ किसी बड़े व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब होने की बात कहते हैं। ट्रंप और उनके सहयोगी इससे पहले भी कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी जमीन पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ट्रंप की बातों पर विश्वास न करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि वे अपनी ही कही बातों से पलटने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्हें उस कानून पर अमल होने से पीछे हटना पड़ा, जिसके तहत भारत और चीन समेत उन पांच देशों पर सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी थी, जो रूस से तेल आयात करते हैं। अमेरिका को खुद रूस से डीजल खरीदने की मजबूरी के चलते अपने कदम वापस खींचने पड़े। यह स्पष्ट है कि अमेरिका-ईरान टकराव और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता पैदा हो चुकी है। तेल और बढ़ती कीमतों की इस तपिश का असर अब अमेरिका पर भी साफ दिखने लगा है, और वह भी ऐसे नाजुक वक्त में जब वहां मध्यावधि चुनाव सिर पर हैं और राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीतिक साख दांव पर लगी हुई है। इन हालात से यह साफ साफ साहज होता है कि अमेरिका को यह अहसास हो चुका है कि मौजूदा ऊर्जा संकट से पार पाने के लिए भारत का सहयोग लेना उसके लिए अनिवार्य हो गया है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का जामनगर स्थित रिलायंस रिफाइनरी का दौरा करना है, जहां जाने से ठीक पहले उन्होंने भारत को कच्चे तेल की रिफाइनिंग के मामले में एक महाशक्ति करार दिया था। वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका की पूरी कोशिश यह है कि भारत वेनेजुएला से ज्वादा से ज्वादा कच्चा तेल खरीदे और उसे रिफाइन करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजे, ताकि ऊर्जा संकट से जुझ रहे देशों के साथ-साथ खुद अमेरिका को भी बड़ी राहत मिल सके।

आर्थिक हितों पर चोट करते आंदोलन



विकास, निवेश और आजीविका के सामने खड़ी होती नई चुनौतियां

लोकतंत्र की मूल भावना में विरोध दर्ज कराना और असहमति व्यक्त करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, परंतु जब यह विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के रूप में मुख्य सड़कों पर अव्यवस्था तथा अराजकता का रूप ले लेते हैं, तब इसका सीधा प्रभाव देश के आर्थिक ढांचे पर पड़ता है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए आयोजित होने वाले ऐसे प्रदर्शनों न केवल देश की प्रगति की रफ्तार को धीमा करते हैं, बल्कि आम आदमी की रोजी-रोटी, व्यापारिक तंत्र और रोजगार के अवसरों के लिए भी अत्यंत गंभीर संकट खड़ा कर देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए आंदोलनों और उनके चलते लगे प्रतिबंधों का उदाहरण लें तो व्यापारिक संगठनों के अनुसार इससे लगभग दो हजार करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। व्यापारियों की प्रतिनिधि संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि ऐसे विरोध-प्रदर्शनों के चलते दिल्ली में प्रतिदिन औसतन चार सौ करोड़ रुपये का व्यापार प्रभावित होता है। जब मुख्य बाजारों और मार्गों पर अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका प्रभाव केवल बड़े शोरूम या उद्योगपतियों तक सीमित नहीं रहता। इसका सबसे दर्दनाक और प्रत्यक्ष असर रोज कमाकर खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों, दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों, माल होने वाले वाहन चालकों, छोटे थोक विक्रेताओं, रेहड़ी-पटरी वालों और आसपास चाय-नाश्ता बेचने वालों पर पड़ता है। बड़े कारोबारी तो कुछ समय के लिए इस वित्तीय झटके को सह सकते हैं, लेकिन दैनिक आय पर आश्रित परिवारों के लिए एक दिन का काम ठप होना भी उनके भोजन, बच्चों की शिक्षा, कम्परे के किराये और दवाइयों के बजट को पूरी तरह बिगाड़ देता है। विशेषकर त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में, जब व्यापारी अग्रिम भुगतान करके स्टॉक जुटाते हैं, ग्राहक बाजारों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे पूरी आर्थिक शृंखला टूट जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलनों के आर्थिक दुष्प्रभावों को लेकर कई अध्ययन हुए हैं। वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित शोधपत्र %सामाजिक असमानता के व्यापक आर्थिक प्रभाव% में 1990 से 2019 तक के वैश्विक आंकड़ों के विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ है कि सामाजिक अशांति का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक नकारात्मक असर पड़ता है। अशांति की बड़ी घटनाओं के बाद लगभग छह तिमाहियों तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का स्तर औसतन 0.2 प्रतिशत से लेकर एक प्रतिशत तक गिर सकता है। इसका मुख्य कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आने वाली गिरावट, उपभोक्ता मांग में कमी तथा विदेशी व घरेलू निवेशकों के भरोसे का कम होना है।

देखिये

TNI आवाज़

पर हमारे खास कार्यक्रम

रमाकान्त गोस्वामी के साथ...

आपकी आवाज़ के साथ

TNI मुलाकात

देश की जानी-मानी हस्तियों,
जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों
और समाज के प्रेरणादायक
व्यक्तित्वों से **खास बातचीत।**

उम्मीद की एक नई रोशनी

संघर्ष, सफलता और
प्रेरणा की ऐसी कहानियाँ
जो बदल रही हैं
समाज की सोच।

THE UNCOVERED UPDATE

हर उस खबर की
पड़ताल, जो सुर्खियों
के पीछे छिपी **सच्चाई**
को सामने लाती है।

राजस्थान की राजनीति

राजस्थान की राजनीति,
सत्ता, विपक्ष, चुनाव और
बड़े राजनीतिक घटनाक्रम
का **सटीक विश्लेषण** और
एक्सक्लूसिव कवररेज।

रमाकान्त गोस्वामी
संस्थापक एवं प्रधान संपादक
TNI आवाज़

खबरों से आगे, सच्चाई के साथ

अब उपलब्ध
16+ प्रमुख OTT
प्लेटफॉर्म पर

JioTV

Jio Fiber

TATA PLAY

VI TV movies & tv

MXPLAYER

dailyhunt

paytm LIVE TV

shemaro TV

DTH LIVE TV

और भी कई प्लेटफॉर्म पर

www.tniawaaz.in

/tniawaaz

DOWNLOAD NOW
TNI AWAAZ APP

KURY LIFESTYLE

पेशावर, एजेंसी। पाकिस्तान हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को लेकर प्रांतीय पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ सुरक्षाबल अधिकारियों को तलब किया है। बुधवार को अदालत ने 10 दिनों के भीतर उनके टिकाने और कानूनी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने अफरीदी के भाई की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की अफरीदी सुनवाई 3 नवंबर को होगी। अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक, राजधानी पेशावर के पुलिस अधिकारी (सीसीपीओ), मुख्य सचिव और गृह सचिव से पूछा है कि क्या अफरीदी को गिरफ्तार किया गया है या किसी आपराधिक मामले में उतका मार दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 अक्टूबर को बिगडती कानून-व्यवस्था का हवाला दे आपातकाल लागू किया गया था। पीटीआर के कंडे ने अफरीदी के साथ अफरीदी को भी हिरासत में लिया गया था। अफरीदी के भाई मुहम्मद आमिर ने उनकी रिहाई की मांग के लिए दायर याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। याचिका के मुताबिक, अफरीदी को हथियारबंद और नकाबपोश लोगों ने पेशावर में सीसीपीओ की मौजूदगी में अगवा किया था और आपातकाल या गवर्नर शासन लागू होने का हवाला देकर अफरीदी को अवैध तरीके से हिरासत में रखने को सही नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल घोषित किया था।

आइए, मिलकर अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करें।

स्पीकर वासुदेव देवनानी ने स्व. भैरोंसिंह शेखावत के स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी शुक्रवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पहुंचकर पूर्व मुख्ेयमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. श्री भैरोंसिंह शेखावत की 103वीं जयंती के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने स्व. शेखावत के समाधि स्ेथल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री देवनानी ने स्व. भैरोंसिंह शेखावत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरण करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनसेवा, सुशासन और लोककल्याण के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने राजस्थान के विकास तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचार, आदर्श और जनकल्याणकारी दृष्टिकोण सदैव समाज एवं भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि स्व. शेखावत का जीवन सार्वजनिक जीवन में समर्पण, सादगी और कर्तव्यनिष्ठा का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे, मुख्ेयमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्ेयमंत्री श्रीमती दीपा कुमारी, सांसद श्री मदन रावैड, श्री सतीश पुनियां, पूर्व विधायक श्री नरपत सिंह राजवी सहित अनेक गणमान्ेय एवं स्ेव. शेखावत के परिजन मौजूद थे।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोंसिंह शेखावत को अर्पित की श्रद्धांजलि



द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. भैरोंसिंह शेखावत की 103वीं जयंती पर विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पहुंचे। उन्होंने स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्व. शेखावत को नमन किया। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने स्व. शेखावत के परिजनों से मुलाकात की तथा श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उपमुख्यमंत्री दिपा कुमारी, सांसद मदन रावैड, सतीश पुनिया, विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

श्रीगंगानगर स्थापना दिवस- 2026 खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम



द अनकवर्ड अपडेट

श्रीगंगानगर। जिला प्रशासन श्रीगंगानगर के तत्वावधान में श्रीगंगानगर स्थापना दिवस-2026 के उपलक्ष्य में महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को प्रतियोगिताओं के अंतर्गत छात्र-छात्राओं के बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन तथा 100 मीटर दौड़ के मुकाबले आयोजित किए गए, जिनमें खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी खेल प्रतिका का प्रदर्शन किया। बास्केटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम आज खेले गए मुकाबले में सेक्रेड हार्ट स्कूल ने डीपी स्कूल को 43 के मुकाबले 51 अंकों से पराजित किया। छात्रा वर्ग में गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल, श्रीगंगानगर ने पीएम श्री मरका चौक स्कूल को 14 के मुकाबले 18 अंकों से हराया। वहीं, एसोसिएशन क्लब ने सेक्रेड हार्ट स्कूल को 28-15 के अंतर से पराजित कर जीत दर्ज की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस इंसपेक्टर एवं कबड्डी के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी श्री नगेन्द्र सिंह ने शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों से परियत्र प्राप्त किया तथा उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न खेल मुकाबलों का आनंद भी लिया और खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी श्री हरजिंदर सिंह बराड सहित श्री महेंद्र गोदार, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, श्री कृष्ण कुमार, श्री नवदीप शर्मा, श्री जगदीप सिंह (जूडो कोच), श्री बलविंदर सिंह, डीपी श्री करण सिंह, श्री सनी कुमार, श्री मोहित कुमार, श्रीमती नीलम रानी, श्री मनोज धारीवाल एवं श्री अजय कुमार ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में निर्णायक एवं आयोजन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंदर सिंह ने भी महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम पहुंचकर चली रही खेल प्रतियोगिताओं का अवलोकन किया। प्रतियोगिता में शनिवार सुबह बास्केटबॉल के सभी सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।

स्पीकर देवनानी ने शदाणी दरबार के माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर डाक टिकट का किया अनावरण

राष्ट्रपति ने माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया,

देवनानी समारोह में हुए सम्मिलित

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रायपुर (छत्तीसगढ़) स्थित पूज्य शदाणी दरबार में आयोजित कार्यक्रम में शदाणी दरबार की पांचवीं पीठाधीश माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट जारी किया। श्री देवनानी ने कहा कि माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर डाक टिकट जारी करना उनके आध्यात्मिक योगदान एवं सेवा परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। संत-महापुरुषों का जीवन समाज को सेवा, सद्भाव, संस्कार और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शदाणी दरबार की समृद्ध धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा भारतीय



संस्कृति और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह डाक टिकट माता साहिब हासी देवी के जीवन एवं योगदान को स्मरण करने के साथ ही उनकी प्रेरणाओं को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। श्री देवनानी ने माता साहिब हासी देवी के

जीवन, आध्यात्मिक योगदान एवं शदाणी दरबार की धार्मिक परंपराओं के महत्व को स्मरण करते हुए कहा कि डाक टिकट का विमोचन उनकी स्मृति को संजोने तथा उनके आध्यात्मिक योगदान को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। समारोह को इंदौर के सांसद श्री शंकर

कृषि आदानों की गुणवत्ता जांच में राजस्थान सरकार की ऐतिहासिक पहल, अब कृषि आदानों के नमूनों की जांच होगी फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पारदर्शी

कृषि विभाग एवं डाक विभाग के बीच महत्वपूर्ण समझौता, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्ट्यचार के प्रति 'जोरो टॉलरेंस' की नीति की अनुपालना में कृषि विभाग ने किसानों के हितों की सुरक्षा, कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। कृषि विभाग ने प्रदेश में बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों के नमूनों की जांच प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, गोपनीय, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को पंत कृषि भवन में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार एवं भारतीय डाक विभाग (राजस्थान परिमण्डल) के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) साइन किया गया। इस समझौते के माध्यम से कृषि आदानों के नमूने एकत्र करने से लेकर उन्हें प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने, परीक्षण करने तथा जांच परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल एवं व्यवस्थित



बनाया जाएगा।

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नमूना लेने वाले निरीक्षक को यह जानकारी नहीं होगी कि नमूना किस प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा और प्रयोगशाला को भी संबंधित डीलर अथवा निर्माता की पहचान की जानकारी नहीं होगी।

कृषि आदानों की जांच व्यवस्था में बड़ा सुधार

वर्तमान में कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर नमूने लेकर प्रयोगशालाओं में जांच कराई जाती है। इस प्रक्रिया में नमूनों के संग्रहण, पैकिंग, परिवहन, प्रयोगशाला आवंटन तथा परीक्षण परिणामों के

प्रबंधन में अनेक स्तरों पर मानवीय हस्तक्षेप की संभावना रहती है। नई व्यवस्था में AgriQMS मोबाइल ऐप एवं भारतीय डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवाओं के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे नमूनों की अदला-बदली, पहचान उजागर होने, अनावश्यक देरी तथा परीक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसी संभावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिलेगी। निरीक्षक मौके पर ही डिजिटल माध्यम से लेंगे नमूने

नई व्यवस्था के अंतर्गत कृषि आदान निरीक्षक AgriQMS मोबाइल ऐप के माध्यम से मौके पर ही नमूना संग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। नमूना लेते समय नमूना संग्रहण स्थल की जीपीएस आधारित जियो-टैगिंग की जाएगी तथा संबंधित उत्पाद देरी तस्वीरें, उत्पाद के विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज डिजिटली लिए जाएंगे। नमूने की पहचान के लिए सिस्टम द्वारा क्यूआर कोड जनरेट किया जाएगा। साथ ही नमूने को सुरक्षित रखने के लिए टैम्पर-प्रूफ पैकिंग की जाएगी। इस व्यवस्था से नमूना संग्रहण का डिजिटल रेकार्ड उपलब्ध होगा तथा बाद में रेकार्ड में अनधिकृत बदलाव अथवा नमूने से छेड़छाड़ की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा।

राज्यपाल बागडे ने बेंगलुरु स्थित ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ में आयोजित समारोह में भाग लिया

आर्ट ऑफ लिविंग’ के प्रणेता श्री श्री रविशंकर से विभिन्न विषयों पर संवाद किया

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने बेंगलुरु स्थित ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ की स्थापना के 45 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ के प्रणेता श्री श्री रविशंकर से संवाद करते हुए उनके 70 वें जन्मदिन को ‘सुशासन, सामाजिक सामंजस्य, शांति और सतत विकास’ के अलोक में समारोहपूर्वक मनाए जाने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में मानवीय मूल्यों, शांति एवं सद्भाव के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर



भारत की सनातन संस्कृति के प्रसार में रही उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि सामंजस्य, शांति और सतत विकास’ के अलोक में समारोहपूर्वक मनाए जाने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी के अवदान की चर्चा करते हुए कहा कि ज्ञान मृत्यु से भी नहीं डरता। उन्होंने कठोपनिषद में यम-नचिकता के प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि ज्ञान परम्परा का

अर्थ है, सतत चलने वाली दृष्टि। परम्परा का अर्थ जड़त्व नहीं बल्कि युगीन संदर्भों को सहेजते हुए जीवन के उदात्त मूल्यों का प्रसार है। राज्यपाल श्री बागडे ने इससे पहले बेंगलुरु स्थित ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ इंटरनेशनल आश्रम में गौशाला का भी अवलोकन किया और वहां संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली।

एशियन पैरा गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक मिलने पर राज्यपाल बागडे ने दी बधाई

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन सा1 स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी मोना अग्रवाल को, पुरुष बैडमिंटन एकल स्क् स्पर्धा में नवीन शिवकुमार को एवं पुरुषों की रिकर्व डबल्स तीरंदाजी स्पर्धा में

हरविंदर सिंह, विजय सुंडी को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि इनके खेल प्रदर्शन से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। श्री बागडे ने भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के जारी रहने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि देश को अपने इन खिलाड़ियों पर गर्व है।